# सांध्य दैनिक 4PM

जिद...सच की

www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_Sanjay YouTube @4pm NEWS NETWORK

● वर्ष: 10 ● अंक: 196 ● पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, गुरुवार, 22 अगस्त, 2024

मूल्य ₹ 3/-

अगर शांति चाहते हैं तो लोकप्रियता से बचिए।
-अब्राहम लिंकन

जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल... 8 | बड़ी रपटीली हैं जम्मू-कश्मीर की... 3 | युवाओं की ताकत के आगे हारी... 2


# सच दिखाने में डर कैसा : अविनाश

## 4PM म्यूजिक चैनल की लॉन्चिंग पर फिल्म निर्देशक ने संपादक संजय शर्मा से की बातचीत

### » अनारकली ऑफ आरा से पाई थी लोकप्रियता

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। अनारकली ऑफ आरा व शी जैसी फिल्मों के जरिये समाज को आईना दिखाने वाले पत्रकार से फिल्म निर्देशक बने अविनाश दास ने देश के प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल 4पीएम के 60 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने व 4पीएम म्यूजिक चैनल की लॉन्चिंग के अवसर पर 4पीएम चैनल के संपादक व वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा से बातचीत की। उन्होंने पत्रकारिता से लेकर फिल्म तक पर अपनी बात रखी। एक निर्देशक के डरने के सवाल पर अविनाश कहते हैं कि मोदी सरकार से जो पत्रकार नहीं डरते उन्हीं की श्रेणी का मैं भी डायरेक्टर हूं। मैं बस सच दिखाने का काम करता हूं।

बड़े-बड़े अखबार व चैनल में पत्रकारिता के शीर्ष पर रहे अविनाश दास ने 2017 में रिलीज हुई फिल्म अनारकली ऑफ आरा से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म में स्वरा भास्कर नजर आई थीं। अविनाश ने जी-5 की फिल्म रात बाकी है का भी डायरेक्शन किया था, जो 2021 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा अविनाश नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज शी और एमएक्स प्लेयर की रनअवे लुगाई के डायरेक्शन के लिए भी जाने जाते हैं।

### स्वरा भास्कर की वजह से बना निर्देशक

**स्वरा भास्कर की वजह से मै निर्देशक बना पाया। अविनाश ने बताया कि जब वह मुंबई पहुंचे तो वह स्वरा भास्कर से मिले। उन्हीं को मैने अपनी अनारकली वाली स्क्रिप्ट सुनाई। उन्हीं के घर पर रहकर मैने पूरी कहानी लिखी। बाद स्वरा ने ही कहा मै इस फिल्म में काम करूंगी। उन्होंने आगे बताया कि चूकि कहानी बिहार के आरा जिले संबंधित थी इसलिए हम वहीं शूटिंग करना चाहते थे पर वहां पर सहूलियत नहीं थी तब कई शहरों की तलाश के बाद यूपी का अमरोहा बिल्कुल आरा की तरह लगा और हमने यहीं पर फिल्म का दृश्याकंन किया।**

### मीडिया अपने रास्ते से भटक गया

फिल्म निर्देशक अविनाश दास ने कहा कि मीडिया आज अपने रास्ते से भटक गया है वह बस सत्ता का गुणगान कर रहा है जो लोकतंत्र के लिए घातक है। उन्होंने आगे कहा किसी काम में लंबे समय से रहने पर वो आपकी शख्सियत का हिस्सा हो जाता है, उससे आप चाह कर भी छूट नहीं पाते। जब मैं पत्रकारिता में गया था या फिर सिनेमा में हूं, दोनों ही जगह कहानियां कहने की बात है। पत्रकारिता में आप समाज की कहानियां कहते हैं। दास ने कहा अभिनेताओं और फिल्म जगत के लोगों के प्रति भावना और देश में बढ़ती असहिष्णुता अनुचित है।

### आमिर से प्रेरित होकर आया फिल्मों में

पत्रकारिता छोड़कर फिल्म निर्देशन में आने के सवाल पर दास ने कहा कि 2008-9 में जब उन्हें आभास हुआ कि अब पत्रकारिता उनके हिसाब वाली नहीं रह गई तब से वह बैचेन रहने लगे और तभी उन्होंने छोड़ने का मन बना लिया। उसी समय आमिर खान के एक चर्चित कार्यक्रम सत्यमेव जयते को देखा जिससे वह भी जुड़े थे। तभी उन्होंने सोचा कि जब एक एक्टर मीडिया का काम कर सकता है तो एक मीडिया वाला भी फिल्म कर सकता है। और उन्होंने मुंबई जाने का फैसला कर लिया।

### सेंसर ने कई डायलॉग हटाने के लिए डाला दबाव

सरकार के द्वारा कैसे दबाव डाला जाता है इसपर भी अविनाश ने बेबाक तरह से अपनी बात बताई। उन्होंने बताया कि एक फिल्म इन गलियों में उन्होंने बनाई है। जिसमें भारत के एकता, मोहब्बत व भाईचारें को लेकर इसकी कहानी रची गई है। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड में भेजा गया तो वहां पर कुछ डायलॉग को हटाने के लिए कह कर प्राइमरी बोर्ड के सदस्य ने इसे रिवाइजिंग कमेटी को भेज दिया। उन्होंने बताया कि सेंसर बोर्ड को एक चायवाले में एटीट्यूड आ गया है, देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली की राजधानी नागपुर व देश के गद्दारों को गोली मारों सालों को,डायलॉग पर आपत्ति थी। उन्होंने कहा यह कोई गाली नहीं है इसलिए वह अब इस मामले को लेकर वह हाईकोर्ट पहुंच गए है।

### 'इन गलियों में' दिखेगा लखनऊ

अविनाश दास ने कहा उनकी एक सामाजिक समस्सता व सीधी-साधी मोहब्त दिखाने वाली फिल्म 'इन गलियों में' 6 सितंबर को रिलीज होगी। उन्होंने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग लखनऊ मे हुई । उन्होंने इस फिल्म में आज कल जो देश में नफरत का माहौल बना हुआ उसको दिखाने का प्रयास किया है। इस फिल्म को इम्तियाज अली बना रहे हैं। इसमें भाग्य श्री की बेटी, नसीरुद्दीन शाह के बेटे व जावेद जाफरी काम कर रहे हैं।

### स्मृति ईरानी के ऑफर को ठुकराया

कश्मीर फाइल्स व केरला स्टोरी जैसी एजेंडे वाली फिल्मों को लेकर अविनाश ने कहा कि इस तरह की फिल्में ठीक नहीं है ऐसी फिल्में बनाकर मै उन लोगों को चेहरा नहीं दिखा सकता जिनके साथ मै दिन-रात, सुख-दुख में खड़ा रहा। इसी पर एक वाक्या भी उन्होंने सुनाया कि एकबार पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें कश्मीर पर एक स्क्रिप्ट दी थी जिसके लिए उन्होंने 30 करोड़ देने की बात कही और फिल्म को छह महीने में पूरा करने को कहा पर उन्होंने ये कहकर उसको मना कर दिया इतने कम समय में वह फिल्म नहीं बना सकते।

# युवाओं की ताकत के आगे हारी भाजपा : अखिलेश

बोले- इसलिए बैंक ने रद्द किया शिक्षकों से वसूली फरमान

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर करारा हमला बोला है। सपा प्रमुख ने सोशल साइट एक्स पर कहा कि 69000 शिक्षक भर्ती कोर्ट से निरस्त होते ही बांदा जिले के कॉपरेटिव बैंक ने भर्ती हुए शिक्षकों से, बैंक से लिए गए किसी भी प्रकार के ऋण की वसूली का फरमान जारी कराकर और आगे भी किसी भी प्रकार के लोन का रास्ता बंद करने की साजिश रची परंतु युवाओं के आक्रोश के आगे ये फरमान एक दिन भी टिक नहीं पाया और भाजपा सरकार को इसे भी रद्द करने का आदेश निकालना पड़ गया लेकिन याद रहे उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ये काम मन से नहीं दबाव से कर रही है, इसीलिए इस आदेश को पूरी तरह रद्द नहीं बल्कि कुछ समय के लिए स्थगित मानकर इसका भरपूर विरोध जारी रखना चाहिए।

वैसे तात्कालिक रूप से ये युवा विरोधी भाजपा के विरूद्ध युवा-शक्ति की एकता की जीत है। जिन भर्ती हुए शिक्षकों ने अपने घर-परिवार और बाकी सामान के लिए नौकरी की निरंतरता की उम्मीद पर कुछ लोन लिया था तो क्या अब ये सरकार उनके घरों और सामानों को कब्जे में लेने की साजिश कर रही है। ये निहायत शर्मनाक कृत्य है कि भाजपा परिवारों को दुख-दर्द देकर सत्ता की धौंस दिखाना चाहती है।

## भाजपा सरकार की बदनीयत की फजीहत

शिक्षक भर्ती में उप्र की भाजपा सरकार की बदनीयत की जिस तरह फजीहत हुई है, शायद उसका बदला वो अभ्यर्थियों से लेना चाहती थी। तभी ऐसे फरमान निकलवा रही है। इससे पहले से ही नौकरी खोने के डर से डरे हुए शिक्षकों पर अत्यधिक मानसिक दबाव बढ़ेगा। जब इन लोन की वसूली के लिए बैंक उनके घरों पर जाएगा तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचेगी। इसके दूरगामी नकारात्मक परिणाम निकलेंगे क्योंकि आर्थिक-सामाजिक-मानसिक रूप से प्रभावित शिक्षक का असर शिक्षण पर भी पड़ेगा, जिससे प्रदेश के बच्चों की शिक्षा और उनका भविष्य भी प्रभावित होगा। इसका एक गहरा आघात भर्ती हुए उन शिक्षकों के जीवन पर भी पड़ेगा, जिन्होंने विवाह करके अपना नया-नया वैवाहिक जीवन शुरू किया था और अपने परिवार को पालन-पोषण इसी नौकरी के आधार पर कर रहे थे। वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी सिर्फ परिवार वाले ही जानते हैं। जनता और परिवारवालों को दुख देकर न जाने भाजपा को क्या सुख मिलता है।

# केंद्रीय परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे नेता प्रतिपक्ष

» राहुल गांधी रायबरेली के साथ अमेठी पर रखेंगे नजर
केंद्र सरकार ने दी हरी झंडी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

रायबरेली। सांसदों की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा के लिए भारत सरकार ने जिला विकास एवं समन्वय अनुश्रवण समिति (दिशा) के सभापतियों की घोषणा कर दी है। नेता प्रतिपक्ष व सांसद राहुल गांधी को रायबरेली के साथ अमेठी में भी केंद्रीय योजनाओं में खामियां खंगालने का मौका दिया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उन्हें अमेठी संसदीय क्षेत्र में दिशा के लिए विशेष आमंत्री नामित किया है। केंद्र में नई सरकार बनने के बाद आगामी अक्टूबर में दिशा की पहली बैठक हो सकती है। जिले स्तर पर सांसदों की अध्यक्षता में हर तीन माह में दिशा की बैठक की व्यवस्था की गई है। दिशा में जिले का सांसद सभापति होता है। इसके अलावा विधायक, एमएलसी, ब्लॉक प्रमुख सदस्य होते हैं।

## किशोरी लाल संभालेंगे सभापति की कुर्सी

जिले में जब तक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में दिशा की बैठक हुई, किशोरी लाल शर्मा सांसद प्रतिनिधि के रूप में बैठक में शामिल हुए। इस बार अमेठी में होने वाली दिशा की बैठक में वे खुद सांसद होने के नाते सभापति की कुर्सी संभालेंगे। विशेष आमंत्री होने के कारण राहुल गांधी बगल की कुर्सी पर बैठक सकते।

सभापति आठ अन्य सदस्यों को स्वयं नामित करता है। केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद भारत सरकार ने दिशा के सभापतियों की घोषणा कर दी है। नेता प्रतिपक्ष व सांसद राहुल गांधी को रायबरेली दिशा का सभापति नामित किया गया है। अमेठी में सांसद केएल शर्मा सभापति बनाए गए हैं, लेकिन राहुल गांधी को दिशा के लिए विशेष आमंत्री नामित किया गया है। यह व्यवस्था पहली बार की गई है। रायबरेली सांसद अमेठी की दिशा की बैठक में विशेष आमंत्री सदस्य के रूप में शामिल हो सकेंगे।

# सही टिकट बंटे तो कांग्रेस जीतेगी 70 सीट : अजय

» बोले-जल्द ही नीतीश कुमार पलटी खाएंगे और एनडीए सरकार गिर जाएगी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चरखी, दादरी। कांग्रेस ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि मेरिट के आधार पर टिकट बंटे तो कांग्रेस 70 सीटें जीतेगी। उन्होंने विधायक चिरंजीव राव की ओर से डिप्टी सीएम बनने के बयान पर उनका पक्ष लिया है। यादव ने चरखी दादरी में आयोजित ओबीसी कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि चिरंजीव राव सिटिंग एमएलए हैं तो उनका टिकट भी पक्का है।

चिरंजीव ने डिप्टी सीएम की जो बात कही है, वह गलत नहीं है। सपने कोई भी देख सकता है। साथ ही दीपक बाबरिया के बयान पर कहा कि वह चाहे कुछ कहें, मुझे जो कहना था कह दिया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने गुरुग्राम व भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा की दोनों सीटें खो दीं। अगर सभी पक्षों की सुनी जाती तो हरियाणा में 3 की जगह 8 सीटें कांग्रेस जीत पाती। गुरुग्राम से मुझे टिकट मिलता तो जीत पक्की थी। इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मेरिट के आधार पर टिकटों का सही वितरण किया तो 70 पार सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार पलटी खाएंगे और एनडीए सरकार गिर जाएगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाएगा। अजय यादव ने आरक्षण को लेकर 21 को भारत बंद के एलान का भी समर्थन किया। अजय यादव ने किरण के राज्यसभा में जाने की चर्चाओं पर कहा कि किरण अगर मेरे से पूछतीं तो मैं कांग्रेस छोड़ने की सलाह नहीं देता। कांग्रेस से इंद्रजीत, बीरेंद्र सिंह, धर्मबीर सहित अन्य बड़े नेता भाजपा में गए और आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अजय यादव ने कहा कि विनेश फोगाट राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुई हैं। विनेश के खाते में पैसे डालने के बारे में प्रदेश सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। राज्यसभा के लिए विनेश की उम्र आड़े आई है।

# हरियाणा में आकाश व अभय ने संभाला मोर्चा

» इनेलो-बसपा को प्रत्याशियों की तलाश

» दूसरे दलों के बागियों पर भी नजर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन कर उतरने वाली इनेलो और बसपा को मजबूत प्रत्याशियों की तलाश है। फिलहाल इनेलो नेता अभय चौटाला और बसपा नेता आकाश आनंद प्रदेश के अलग-अलग हलकों में जाकर संगठन को मजबूती दे रहे हैं और प्रत्याशियों का फीडबैक ले रहे हैं।दोनों पार्टियां सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान कर चुकी हैं, लेकिन सभी सीटों पर प्रत्याशी उतराना चुनौती बना हुआ है।

ऐसे में दोनों ही दलों को भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची जारी होने का इंतजार है। इसके बाद जिन नेताओं की टिकटें कटेंगी, इनेलो-बसपा उन पर दांव खेलने की तैयारी में हैं। प्रदेश की 90 में से 53 सीटों पर इनेलो और 37 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी। बेशक चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक दोनों दल अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र तय नहीं कर पाए हैं, कि कहां से किस दल के प्रत्याशी उतारे जाएंगे। इनेलो के लिए यह चुनाव और भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि उस पर चुनाव चिह्न चश्मे का निशान तक छीनने की नौबत आई हुई है। इनेलो नेता अभय चौटाला खुले तौर पर कह चुके हैं कि अगर कोई और दल उनके साथ समझौता करता है तो इनेलो कुछ सीटें उसके लिए छोड़ सकता है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनेलो के पास अभी सभी सीटों पर मजबूत प्रत्याशी नहीं हैं।

## आरक्षित सीटें बसपा के खाते में जा सकती हैं

संभावना है कि प्रदेश की आरक्षित 17 सीटों पर बसपा अपने उम्मीदवार उतार सकती है। क्योंकि यहां पर दलित वोट बैंक अधिक है और यहां पर अलग-अलग दलों से कई-कई नेता टिकट की दौड़ में हैं। ऐसे में बसपा को उम्मीदवार मिलने में आसानी रहेगी। इसके अलावा जहां-जहां पहले बसपा मजबूत स्थिति में रही है, वहां पर भी पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। इनमें यमुनानगर जिले के छछरौली, जगाधरी, करनाल के असंध समेत अन्य विधानसभा क्षेत्रों से बसपा अपने प्रत्याशी उतार सकती है।

## जम्मू-कश्मीर में दम दिखाएगी बसपा

वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में कदुआ विधानसभा सीट पर 31.65 फीसदी वोट पाकर बसपा सभी दलों को चौंका चुकी है। बेशक 39 फीसदी वोट पाकर भाजपा को जीत मिली लेकिन बसपा का ग्राफ ऊपर आने से कांग्रेस चौथे स्थान पर खिसक गई। अब विस चुनाव 2024 में भी बसपा ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। विधानसभा चुनाव 2014 में कदुआ जिले में कई रोचक फेरबदल भी हुए। यहां पूर्व विधायक समेत 44 प्रत्याशियों की जमानत जनता जब्त करवा चुकी है।

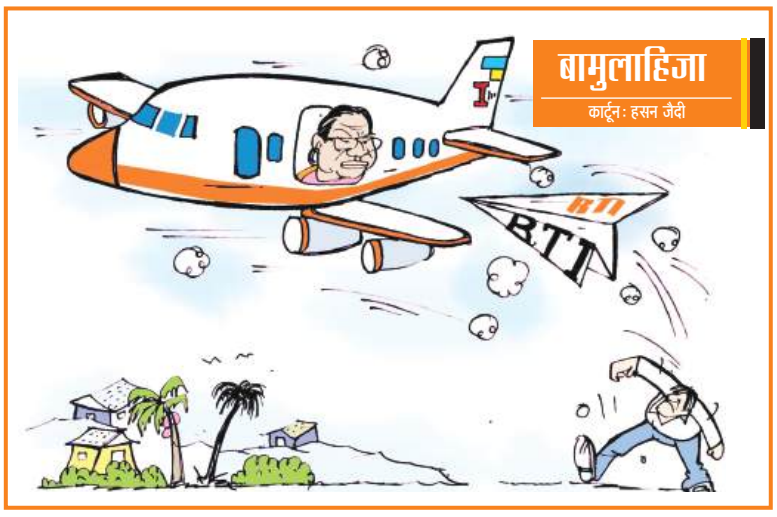


# कांग्रेस का केंद्र को सुझाव

» जनगणना प्रश्नावली में अतिरिक्त कॉलम जोड़कर जुटा सकते हैं ओबीसी डाटा : जयराम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। जातिगत जनगणना की मांग कर रही कांग्रेस ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का जातिगत डाटा जुटाने को लेकर केंद्र सरकार को सुझाव दिया है। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि वह 1951 से जनगणना के जरिये जुटाए जा रहे एससी-एसटी के डाटा की तरह की ओबीसी का डाटा संकलित कर सकती है।

इसके लिए सरकार को जनगणना प्रश्नावली में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़ना होगा। विपक्षी पार्टी ने कहा कि इस कदम से सक्रिय योजनाओं के क्रि यान्वयन के लिए ठोस आधार मिलेगा। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि केंद्र सरकार ने अगली जनगणना को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है। मगर इन दिनों जातिगत जनगणना के लिए डाटा संकलित करने को लेकर चर्चा चल रही है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है। मगर 2021 से अब तक जनगणना नहीं हुई है।

# बड़ी रपटीली हैं जम्मू-कश्मीर की चुनावी राहें

» पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी

» भाजपा, कांग्रेस तलाश रहें साथी, पीडीपी व नेंका भी मोर्चे पर डटे

» गुलामनबी आजाद पर भी बढ़ा दबाव

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में दस वर्ष बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना भी जारी हो गई। इसी के साथ उम्मीदवारों के नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। चुनाव आयोग मतदाताओं की फाइनल सूची भी प्रकाशित किया गया। वहीं राज्य की सियासी पार्टियों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस, बीजेपी, नेशनल कांफ्रें स, पीडीपी से लेकर हर छोटा-बड़ा दल जीत की जुगत में लग गया है। सब अपने समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करने के लिए रास्ते तलाश करने में जुटे हैं।

पहले चरण में सात जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण के लिए 27 अगस्त तक नामांकन भरे जाएंगे। 28 को पर्चों की जांच होगी और 30 अगस्त तक नामांकन वापस लिए जा सकते है। 19 सितंबर को मतदान होगा। वहीं इन इलाकों में सुरक्षाबलों की तैनाती भी शुरू कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार सात जिलों अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा, डोडा, किश्तवाड़ व रामबन की 24 सीटों के लिए 27 अगस्त तक नामांकन होगा। हालांकि, पहले दिन किसी भी सीट पर पर्चा दाखिल नहीं किया गया। इस बीच विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। प्रदेश में कुल 8878832 मतदाता 90 विधायकों का चुनाव करेंगे। इनमें 75812 सर्विस वोटर हैं।

## चुनावी घोषणा के बाद सियासी दल सक्रिय

### महबूबा की बेटी इल्तिजा भी दिखाएंगी दम

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने आठ विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। बिजबिहाड़ा की पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। माना जा रहा है कि इन प्रभारियों को ही अंतिम मौके पर पार्टी प्रत्याशी घोषित करेगी। इल्तिजा मुफ्ती विधानसभा चुनाव से अपने राजनीतिक करिअर की शुरुआत करेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को इन प्रभारियों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक बुलाई थी। बैठक में चुनाव आयोग की तीन चरणों में चुनाव करवाने की घोषणा का स्वागत किया गया। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर पुलिस और नौकरशाही में बड़े पैमाने पर किए गए फेरबदल की आलोचना करते हुए चुनाव की निष्पक्षता के बारे में चिंता जताई गई। इल्तिजा ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से होने चाहिए। बैठक के बाद पीडीपी पार्टी प्रवक्ता ने आठ प्रभारियों की सूची जारी की। इसके साथ ही राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि इन प्रभारियों को ही अंतिम मौके पर पार्टी प्रत्याशी घोषित करेगी। सामान्य तौर पर मान्यता है कि जिन लोगों को हलकों का प्रभारी बनाया जाता है उन्हीं लोगों को उस क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया जाता हैं।

### पहले चरण में यहां मतदान

राज्य में पुलवामा के पांपोर, त्राल, राजपोरा, अनंतनाग के डोरू, कोकरनाग, अनंतनाग पश्चिम, अनंतनाग, बिजबिहाड़ा, शांगस, पहलगाम, शोपियां के जैनपोरा व शोपियां, कुलगाम के डीएच पोरा, कुलगाम व देवसर, रामबन के रामबन व बनिहाल, किश्तवाड़ के इंदरबल, किश्तवाड़, पाडर और डोडा के भद्रवाह, डोडा और डोडा पश्चिम सीटों के लिए चुनाव होगा।

### भाजपा ने रेड्डी के साथ राम माधव को बनाया चुनाव प्रभारी

भाजपा ने धुरंधर नेता राम माधव को जी किशन रेड्डी के साथ चुनाव प्रभारी बनाया है। जम्मू-कश्मीर में 2015 में पहली बार पीडीपी के साथ सरकार की पटकथा लिखने में राम माधव की अहम भूमिका रही है। माना जा रहा है कि उनके अनुभवों के आधार पर उन्हें दोबारा जम्मू-कश्मीर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले चरण की अधिसूचना के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता सुहैल बुखारी व डीडीसी डॉ. हरबख्श सिंह, अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष जफर इकबाल मन्हास व उनके बेटे व शोपियां नगर परिषद उपाध्यक्ष इरफान मन्हास, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के महासचिव चौधरी हारुन खटाना ने इस्तीफा दे दिया। वहीं, पीडीपी में दो साल बाद पूर्व मंत्री अब्दुल हक खान शामिल हुए। डॉ. हरबख्श ने बारामुला के सांसद इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी का दामन थाम लिया है। सुहैल ने पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि जफर के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। हालांकि कश्मीर में पार्टी का समर्थन पाने वाले निर्दलीय चेहरों की तलाश की जा रही है। वर्ष 2014 में अनुच्छेद 370, अफस्पा, पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों का भविष्य जैसे मुद्दों पर भाजपा और पीडीपी के नजरिए अलग थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने माधव को पार्टी का मुख्य वार्ताकार बनाकर जम्मू कश्मीर भेजा था। उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर स्व. मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ भाजपा की पीडीपी के साथ सरकार बनी थी। प्रदेश भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं का माधव से संपर्क रहे हैं।

## भाजपा-पीडीपी पर 2014 दोहराने की चुनौती

इस चुनाव मे जहां भाजपा व पीडीपी के लिए 2014 के इतिहास को दोहराने की चुनौती होगी, वहीं, नेकां और कांग्रेस पर पिछले प्रदर्शन को सुधारने का दबाव होगा। आतंकवाद के प्रचंड स्तर पर पहुंचने के बाद जम्मू-कश्मीर में 1996 में सबसे पहला विधानसभा चुनाव हुआ। इसके बाद 2014 तक तीन और विधानसभा चुनाव हुए।

2014 में भयंकर बाढ़ की विभीषिका के बाद हुए आखिरी विधानसभा चुनाव में भाजपा किंगमेकर के रूप में उभरी। पार्टी ने जम्मू संभाग से 25 सीटें झटकते हुए पीडीपी के बाद सबसे अधिक सीटें अपनी झोली में डाली। पीडीपी 28 सीटों के साथ नंबर एक पर रही। हालांकि, भाजपा को मिले मत प्रतिशत सभी पार्टियों से अधिक रहा। इस चुनाव में नेकां और कांग्रेस को काफी नुकसान उठाना पड़ा और उसके हाथ से सत्ता निकल गई। भाजपा और पीडीपी ने मिलकर 2015 में सरकार बनाई। लेकिन गठबंधन की यह सरकार तीन साल ही चल पाई और 2018 में गिर गई। जम्मू-कश्मीर के आखिरी विधानसभा चुनाव 2014 के परिणामों पर सीटों के आधार पर नजर डाली जाए तो भाजपा की झोली में 37 में 25 सीटें आईं।

शेष 12 सीटों में कांग्रेस को छह, नेकां को तीन, पीडीपी को दो व एक निर्दल को जीत मिली। इसी प्रकार कश्मीर की 50 (लद्दाख की चार सीटों को मिलाकर) सीटों में पीडीपी को 26 सीटें मिलीं। शेष 24 सीटों में नेकां को 12, कांग्रेस को छह, निर्दल को छह सीटें मिलीं। भाजपा के हाथ एक भी सीट नहीं आई। इसलिए जम्मू संभाग में भाजपा को पिछले प्रदर्शन दोहराने की चुनौती होगी। ज्ञात हो कि विधानसभा में लद्दाख की चार सीटों को मिलाकर 87 सीटें थीं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख को बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है इसके बाद यहां विस सीटों की संख्या 83 रह गई। परिसीमन के बाद सीटें बढ़कर 90 हो गईं। इनमें जम्मू में छह सीटें बढ़ाकर 43 और कश्मीर में एक सीट बढ़ाकर 47 करने के साथ ही सत्ता संतुलन बनाने की कोशिश की गई।

## अपनी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र

श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी ने चुनावी घोषणापत्र जारी किया है। पार्टी मुख्यालय में पार्टी का चुनावी घोषणापत्र जारी करने के बाद पार्टी के महासचिव मोहम्मद रफी मीर ने मीडिया को संबोधित किया। पार्टी ने सत्ता में आने के बाद स्थानीय युवाओं के लिए भूमि और नौकरी की सुरक्षा के लिए संवैधानिक गारंटी सुनिश्चित करने का दावा किया है। अपनी पार्टी ने दावा किया है कि राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए अथक प्रयास करेंगे, साथ ही अपनी पार्टी जम्मू और कश्मीर की संस्कृति और विशेष पहचान को संरक्षित करने के लिए संवैधानिक गारंटी देगी, कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में अनुच्छेद 371 के प्रावधानों के समान। इसमें भूमि और नौकरी की सुरक्षा शामिल है।

## मल्लिकार्जुन खरगे व राहुल संभालेंगे मोर्चा

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आगामी विधानसभा चुनावों से पहले महत्वपूर्ण बैठकों के लिए जम्मू-कश्मीर का दो दिवसीय दौरा पर पहुंचे। वह शाम को करीब साढ़े पांच बजे जम्मू पहुंचेंगे। पूर्व में दोनों नेताओं के पहले जम्मू और फिर श्रीनगर जाने का कार्यक्रम था। लेकिन अब वे श्रीनगर से अपना दौरा शुरू करेंगे, एआईसीसी महासचिव गुलाम अहमद मीर ने यह जानकारी दी है। श्रीनगर में मीर ने कहा कि दोनों नेता गुरुवार को श्रीनगर में कश्मीर घाटी के 10 जिलों में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। वे चुनावों के लिए जमीनी स्तर की तैयारियों के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। राहुल गांधी के दौरे में इसलिए बदलाव किया कि कांग्रेस भारत बंद को प्रभावित नहीं करना चाहती। सूत्रों का दावा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के साथ राहुल गांधी की बैठक भी हो सकती है। पार्टी को उम्मीद है कि बैठक में गठबंधन का रास्ता साफ हो सकता है। 90 सदस्यीय जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए तीन चरणों में चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और एक अक्तूबर को होंगे। वहीं अभी श्रीनगर के एक सांच सितारा होटल में दोनों दलों के पांच-पांच नेताओं की मौजूदगी में बातचीत शुरू हुई। सब कुछ ठीक रहा तो अगले चार-पांच दिनों में गठबंधन की घोषणा हो जाएगी। सूत्रों ने बताया, दोनों पार्टियों के आलाकमान के निर्देश पर बातचीत का सिलसिला शुरू किया गया। इसके लिए कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा, कार्यकारी अध्यक्ष ताराचंद व रमण भल्ला तथा पूर्व अध्यक्ष जीए मीर व विकार रसूल वानी तथा नेकां से कश्मीर संभाग के अध्यक्ष नसीर असलम वानी, जम्मू संभाग के अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता, सकीना इट्टू, खालिक सुहरावर्दी तथा अतिरिक्त महासचिव अजय सडोत्रा को नामित किया गया है। सूत्रों के अनुसार, पहली बैठक में इस बात पर मंथन किया गया कि जहां जिस पार्टी की दमदार उपस्थिति हो उसे उसके खाते में दिया जाए। परिसीमन के चलते कई विधानसभा हलकों का समीकरण बदल गया है। इस वजह से सिटिंग-गेटिंग का फार्मूला अनुकूल नहीं होगा। मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सीटों के बंटवारे का फैसला किया जाए। बातचीत में यह पक्ष भी सामने आया कि गठबंधन के तहत जिस पार्टी को सीटें आवंटित होंगी वह अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगा। उस सीट पर गठबंधन सहयोगी पूरी मदद करेगा। चुनाव प्रचार संयुक्त रूप से किया जाएगा। पहले चरण की 24 सीटों के लिए सबसे पहले गठबंधन में साझा होने वाली सीटों की जानकारी को सार्वजनिक किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि भाजपा को रोकने के लिए यह गठबंधन आकार लेगा। समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाया गया है।

## नेकां ने राज्य में खुशहाली के लिए किए 12 चुनावी वादे

श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने घोषणापत्र जारी करने के बाद कहा कि पार्टी केवल पूरे होने वाले वादे ही कर रही है। उन्होंने घोषणापत्र को नेशनल कॉन्फ्रेंस का दृष्टिकोण पत्र और शासन के लिए रोडमैप बताया। घोषणापत्र में शामिल 12 वादों में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 और केंद्र शासित प्रदेश के बिजनेस एक्ट 2019 को फिर से तैयार करने का जिक्र है। घोषणापत्र में मुख्य मुद्दा अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली है। इसके साथ ही वर्ष 2000 से पूर्व विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता प्रस्ताव को लागू करने का वादा किया गया है। पार्टी के घोषणापत्र में युवाओं व महिलाओं को लुभाने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर आम मतदाताओं को भी अपने पक्ष में करने का प्रयास किया गया है। घोषणापत्र में लगभग सभी वर्गों को छूने की कोशिश की गई है। गौरतलब हो कि जबसे राज्य में 370 हटा है तब से पूर्व सीएम व केंद्रीय मंत्री इस मुद्दे पर हर मंच पर मुखर रहते हैं। इस चुनाव में इसको लेकर वह और आक्रामक रहेंगे।

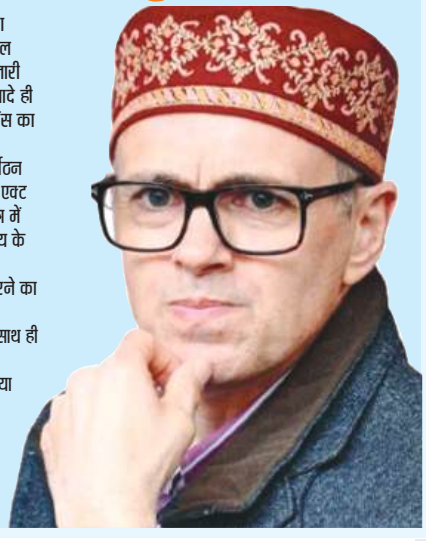

# जश्न-ए-4PM में मीडिया से लेकर साहित्य व राजनीति के कई दिग्गजों ने की शिरकत

**4PM** को लोगों का प्यार निरंतर मिलता जा रहा है। जिसके चलते 4PM आए दिन नई-नई उपलब्धियां छू रहा है। इसी क्रम में 4PM के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। लोगों के प्यार की बदौलत 4PM का सफर अब 6 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच चुका है। देश के नंबर वन यूट्यूब चैनल 4PM के 6 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने पर 4PM की पूरी टीम ने जश्न मनाया। इस जश्न-ए-4PM में पत्रकारिता से लेकर साहित्य, कला और राजनीति जगत की तमाम दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की। इन हस्तियों का 4PM के संपादक संजय शर्मा ने दिल खोलकर स्वागत व सम्मान किया।

## जिद... सच की

Sanjay Sharma
editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

# मेधावी व योग्यता के मापदंड पर हो चयन

**उच्चतम न्यायालय की जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सौरभ यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य समेत अन्य मामलों के आधार पर कहा कि एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग (आरक्षित वर्ग) के उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित या सामान्य वर्ग की सीटों पर भी क्षैतिज आरक्षण व्यवस्था के तहत दावा करने के हकदार हैं। उन्हें अनारक्षित वर्ग में प्रवेश दिया जाना चाहिए।**

*सुप्रीम कोर्ट ने मेधावी छात्रों के लिए एक अच्छा फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने एक अहम फैसला देते हुए कहा कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार मेरिट के आधार पर अनारक्षित वर्ग की सीटों पर क्षैतिज आरक्षण के आधार पर दावा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसमें आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग की सीटों पर मेरिट के आधार पर एडमिशन देने से इनकार कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय की जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सौरभ यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य समेत अन्य मामलों के आधार पर कहा कि एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग (आरक्षित वर्ग) के उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित या सामान्य वर्ग की सीटों पर भी क्षैतिज आरक्षण व्यवस्था के तहत दावा करने के हकदार हैं। उन्हें अनारक्षित वर्ग में प्रवेश दिया जाना चाहिए।*

*सुप्रीम कोर्ट ने राम नरेश रिंकू और अन्य की तरफ से दायर अपील को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया। यह मामला मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में दाखिला से संबंधित है, जिसमें आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों को सामान्य कोटे में दाखिला देने से इनकार कर दिया गया था। दरअसल, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के नियम 2(जी) के तहत 5 फीसदी सीटें सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले छात्रों के लिए आरक्षित हैं। इनमें जो सीटें बचती हैं और जो अनारक्षित हैं, उन्हें ओपन कैटेगरी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके खिलाफ याचिका दायर की गई। याचिका में मांग की गई कि सीटें ओपन कैटेगरी में स्थानांतरित करने से पहले आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों को, जो सरकारी स्कूल में पढ़ें हैं, उन्हें आवंटित की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दिया है। अपीलकर्ताओं ने कहा कि एक मामले में पारित आदेश को मान्यता न देकर उच्च न्यायालय ने गलती की है। उन्होंने कहा कि नीति के गलत अनुप्रयोग के कारण, एक विषम स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसमें यूआर-जीएस सीटों में, अपीलकर्ताओं की तुलना में बहुत कम मेधावी व्यक्तियों को प्रवेश मिल गया है, जबकि यूआर-जीएस उम्मीदवारों की तुलना में बहुत अधिक मेधावी अपीलकर्ताओं को प्रवेश से वंचित कर दिया गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि खुली श्रेणी सभी के लिए खुली है, और इसमें किसी उम्मीदवार के लिए एकमात्र शर्त योग्यता है, भले ही उसे किसी भी प्रकार का आरक्षण लाभ मिला हुआ है या नहीं। अनारक्षित सीटों से मेधावी आरक्षित उम्मीदवारों को प्रतिबंधित करना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि योग्यता के सिद्धांतों का भी उल्लंघन है।*

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

# खेल नीति में व्यापक बदलाव की जरूरत

जगमति सांगवान

पेरिस ओलंपिक में छह अगस्त को भारतीय खिलाड़ी विनेश फोगाट ने जिस प्रकार एक के बाद एक तीन बाऊट जीती और खास तौर पर अजेय मानी जाने वाली जापानी सुसाकी को हराया, उससे देश में उत्साह और आह्लाद पैदा हुआ। उसने महिला कुश्ती में पहली बार कोई गोल्ड मेडल जीतने की आस जगाई थी। लेकिन सात अगस्त की सुबह सौ ग्राम ओवरवेट होने की वजह से विनेश के डिसक्वालीफाई होने की खबर आते ही देशवासियों का वह आह्लाद विनेश के प्रति भारी हमदर्दी में बदलने लगा। बहरहाल, इस प्रकरण से कुछ लोगों में खेल सिस्टम के खिलाफ अविश्वास भी गहराया। कई फिल्मी हस्तियों व खिलाड़ियों की बयानबाजी, ओलंपिक डेलिगेशन द्वारा सही समय पर अधिकृत बयान न देने, तथा खेल मंत्री द्वारा संसद में पूरे प्रकरण को सिर्फ विनेश की ट्रेनिंग पर खर्च के हिसाब तक सिकोड़ देने का अच्छा संकेत नहीं गया।

इसी प्रकार सेमीफाइनल के उपरांत एकदम विनेश के वेट में अचानक वृद्धि व अन्य कई सवालों का जवाब नहीं मिल रहा। इन निर्णायक क्षणों में आईओए, कुश्ती फेडरेशन, उसके कोच, फिजिशियन की भूमिका पर भी सवाल हैं। ऐसे में सरकारी तंत्र व खेल मंत्रालय को एक श्वेत पत्र के माध्यम से जनता से मुखातिब होना चाहिए। उतना ही जरूरी है हमारी खेल नीति में लिंग संवेदी बदलाव। पेरिस के वकीलों ने ओलंपिक अधिशासी कोर्ट के स्तर पर विनेश की ओर से उसकी कांस्य पदक साझा करने की अपील दर्ज करवा कर एक स्वागतयोग्य पहल की। जनता को विश्वास में लेने के लिए सरकारी तंत्र द्वारा यथासंभव तत्काल समुचित प्रयास करना इसलिए भी अति आवश्यक है क्योंकि इस पूरे प्रकरण की अपनी एक त्रासदीपूर्ण पृष्ठभूमि है। जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। पिछले दिनों चाहे वह हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री पर लगे यौनहिंसा के आरोप हों, कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष व भाजपा के शक्तिशाली पूर्व सांसद बृजभूषण पर विनेश समेत अन्य ओलंपियन खिलाड़ियों द्वारा यौन दुर्व्यवहार के खिलाफ जंतर-मंतर पर लड़ा गया अभूतपूर्व संघर्ष हो, जनता की नजर में सरकार की डीलिंग चुनावी कंसीडरेशन से संचालित रही है।

यह कवायद महिला खिलाड़ियों को न्याय देने वाली नहीं थी। जिसके नकारात्मक असर खेल जगत पर पड़े हैं। यहां सवाल स्वाभाविक है कि न्याय

के लिए आवाज उठाने वाली वह हरियाणा की ओलंपियन एथलीट जूनियर कोच हो या महिला ओलंपिक कुश्ती में देश के लिए पहली मेडल विजेता साक्षी मलिक और अब विनेश फोगाट। इन सभी को आखिर खेल ही क्यों छोड़ना पड़ा है? उनके मनोबल को पितृसत्तात्मक सिस्टम के ठेकेदार कब तक तोड़ते रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बगैर तो एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को क्या इस चीज का अंदाजा नहीं है कि उनके संवेदनहीन व भेदभाव पूर्ण व्यवहार ने इन खिलाड़ियों व राष्ट्रीय गरिमा को कितनी ठेस पहुंचाई है? इन निहित स्वार्थी तत्वों के क्रियाकलापों के कारण कितनी बेटियों को उनके माता-पिता द्वारा खेल से दूर किया गया है? इस आधुनिक युग में भी जिन असंख्य एकलव्यों के अंगूठे कलम किये जा रहे हैं, वक्त उनका हिसाब लेगा। हकीकत में तो पूरे खेल जगत के प्रति ही सरकार का रवैया उपेक्षा पूर्ण नजर आता है। हाल का खेल बजट भी इसकी एक नजीर हो सकता है। इसमें खेलों के लिए बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं जगती। जो खिलाड़ी इस बार पेरिस ओलंपिक में खेले हैं, उनकी अगर केस स्टडी की जाए तो पता लगेगा कि उनके संघर्ष के दौर में तो उनके परिवारों ने ही अपना बजट निचोड़ कर उनके खेल करियर निर्माण पर लगाया है। सरकारें तो मेडल जीतने के बाद ही जो पुरस्कृत करने की होड़ लगाती हैं उसकी आड़ में तो वे अपने ही राजनीतिक स्वार्थ साधते हैं। अपनी इमेज बिल्डिंग करते हैं। राजनीति को चमकाने के लिए इन खिलाड़ियों की उपलब्धियों को भुनाने को लालायित रहते हैं। अभी भी जो लोग खेलों में अपना कैरियर बना रहे हैं, वे वही हैं जिनके परिवारों के पास उनके ऊपर खर्च करने के लिए कुछ सामर्थ्य है।

खास तौर पर महिला खिलाड़ी बनने की आकांक्षा रखने वाली साधारण परिवारों की बेटियों के सपने तो संसाधनों के अभाव में अभी भी आए दिन चूर-चूर हो रहे हैं। उस खेल प्रतिभा व ऊर्जा को हम उपयुक्त सुविधा देकर जब तक खेल दायरे में प्रवेश करवाने की स्थिति में नहीं लाते तब तक हमारी ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाने की तृष्णा केवल मृगतृष्णा ही रहेगी। अत: एक समग्र श्वेत पत्र व हमारी खेल नीति में बदलाव समय की रणनीतिक जरूरत है। जनता में पैदा हुआ अविश्वास आगे तिरस्कार का रूप न ले जाए इसके लिए जिस आमूलचूल परिवर्तन की दरकार है, वह उन सभी संबंधित पक्षों के जन-अभियान छेड़ने से हो पाएगा जो व्यवस्था के भुगतभोगी हैं।

# जलवायु परिवर्तन से पीने योग्य नहीं रहेगा भूजल

मुकुल व्यास

दुनिया में लगभग हर चार में से एक व्यक्ति जीवित रहने के लिए पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद जलाशयों पर निर्भर है क्योंकि साफ पानी की झीलों, नदियों और बांधों तक सभी लोगों की पहुंच नहीं है। वैज्ञानिकों ने चेताया है कि सदी के अंत तक लाखों लोग पानी की इस मामूली आपूर्ति से भी वंचित हो सकते हैं क्योंकि बढ़ते तापमान के कारण उथले भूजल के विषाक्त होने का खतरा है। शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने वैश्विक तापमान वृद्धि के विभिन्न परिदृश्यों के तहत दुनिया भर में भूजल स्रोतों के तापमान परिवर्तनों को सटीक संख्या में बताने के लिए ऊष्मा परिवहन का एक विश्व-स्तरीय मॉडल विकसित किया है। सबसे खराब स्थिति में, 2100 में लगभग 59 करोड़ लोग ऐसे जल स्रोतों पर निर्भर हो सकते हैं जो पीने योग्य पानी के लिए सबसे कड़े मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इस समय गर्मी की लहरें, बर्फ की पिघलती हुई टोपियां और समुद्रों का बढ़ता स्तर नियमित रूप से सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन हमारा ध्यान भूमि पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों की तरफ नहीं जाता।

जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करते हुए हमारा फोकस मौसम की घटनाओं और पानी की उपलब्धता पर रहता है। लेकिन हमें भूजल पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में अधिक व्यापक रूप से सोचने की आवश्यकता है। यह सच है कि हमारे पैरों के नीचे की चट्टान और मिट्टी की परतें समुद्री जल की गर्मी को अवशोषित करने की क्षमता से मेल नहीं खाती हैं। फिर भी,यह आश्चर्यजनक है कि भूजल के गर्म होने के परिणामों पर इतना कम ध्यान दिया गया है, खासकर जब पानी की कमी और रिचार्ज (पुनर्भरण) दर पर इतनी अधिक चर्चा होती है। सतह के ठीक नीचे छिद्रपूर्ण चट्टानों के भीतर फंसा पानी घुले हुए खनिजों, प्रदूषकों और संभावित रोगजनकों से भरा हो सकता है। लेकिन बहुत बड़ी आबादी के समक्ष इस प्रदूषित जल पर निर्भर रहने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। इन भूमिगत जलाशयों को सिर्फ एक या दो डिग्री गर्म करने से परिणाम भयावह हो सकते हैं। इससे पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और खतरनाक बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा मिल सकता है,या आर्सेनिक और मैंगनीज जैसी भारी धातुओं की अत्यधिक मात्रा पानी मे घुल सकती है।

इस अध्ययन की मुख्य लेखिका और जर्मनी के कार्लश्रु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की भू-विज्ञानी सुजैन बेंज के अनुसार दुनिया मे पहले से ही लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे क्षेत्रों में रह रहे हैं,जहां भूजल पीने के पानी के सख्त दिशा-निर्देशों में निर्धारित तापमान से ज्यादा गर्म है। इसका मतलब है कि बिना ट्रीटमेंट के वहां का पानी पीना सुरक्षित नहीं है। आसपास पर्याप्त आकार के सतही जलाशयों वाली आबादी के लिए भी गर्म भूजल उन प्रमुख कारकों को बदल सकता है जो पानी को मानव उपभोग के लिए सुरक्षित रखते हैं। 7.7 करोड़ से 18.8 करोड़ लोगों के ऐसे क्षेत्र में रहने का अनुमान है जहां भूजल 2100 तक पीने योग्य मानकों को पूरा नहीं कर पाएगा। इस अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि भूजल की रक्षा के लिए कार्रवाई करना और भूजल पर जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए स्थायी समाधान खोजना कितना आवश्यक है।

इस बीच, जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक अन्य अध्ययन में वैज्ञानिकों ने दुनिया में मीथेन उत्सर्जन में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, लोगों की गिरती सेहत, गायब होती बर्फ की चादरों और अप्रत्याशित मौसम के रूप में जलवायु परिवर्तन की बड़ी चेतावनियां हमें लगातार मिल रही हैं। फिर भी हम वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की बढ़ती मात्रा को उत्सर्जित कर रहे हैं। इससे हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। विशेषज्ञों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में बताया गया है कि 2006 से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन बढ़ रहा है। 2020 से इसमें तेजी आई है। यदि हम बहुत जल्द कुछ कठोर कदम नहीं उठाएंगे तो उत्सर्जन की यह प्रवृत्ति जारी रहेगी। नए अध्ययन के शोधकर्ताओं ने मीथेन उत्सर्जन रोकने के लिए रणनीतियां तैयार की हैं जिनका उपयोग विभिन्न देश उचित कार्रवाई करने के लिए कर सकते हैं। इसमें मदद करने के लिए उन्होंने एक ऑनलाइन टूल भी विकसित किया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि मीथेन उत्सर्जन में यह निरंतर वृद्धि मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के लगातार उपयोग के कारण है।

मीथेन सीधे तेल,गैस और कोयले की ड्रिलिंग और प्रोसेसिंग द्वारा उत्पादित होती है। अब एक नई बात यह है कि गर्म जलवायु के कारण प्राकृतिक आर्द्रभूमि से मीथेन का बढ़ता उत्सर्जन ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि कर रहे हैं। लैंडफिल, पिघलते हुए पर्माफ्रॉस्ट और पशुधन से भी मीथेन का उत्पादन होता है। अमेरिका में ड्यूक विश्वविद्यालय के जलवायु विशेषज्ञ डू शिंडेल का कहना है कि फिलहाल इन स्रोतों से उत्सर्जन में योगदान मामूली है। हालांकि इन पर भी बारीकी से नज़र रखने की ज़रूरत है। शोधकर्ताओं ने अपने पेपर में लिखा है कि जलवायु परिवर्तन को सीमित करने के लिए दुनियाभर के प्रयास मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड पर केंद्रित हैं। चूंकि मानव जाति कई दशकों से जलवायु परिवर्तन को पर्याप्त रूप से निपटने में विफल रही है, इसलिए अब वार्मिंग को तय लक्ष्यों से नीचे रखने के लिए हमें सभी प्रमुख जलवायु प्रदूषकों पर अंकुश लगाने पड़ेंगे। इस समय हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन की मात्रा बहुत कम है,लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मीथेन एक अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है।

# न्यूयॉर्क में दिखी भारतीय समुदाय की ताकत: पंकज त्रिपाठी

**» फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने किया आयोजन**

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। अभिनेता पंकज त्रिपाठी की हाल में रिलीज हुई फिल्म 'स्त्री 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इस साल पंकज त्रिपाठी न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड में 'गेस्ट ऑफ ऑनर' के तौर पर शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में चुने जाने पर आभार व्यक्त करते हुए पंकज त्रिपाठी ने कहा, मैं ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनकर बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूं, जो भारत की स्वतंत्रता और दुनिया भर में भारतीयों के बीच एकता की भावना का जश्न मनाता है।

उन्होंने आगे कहा, न्यूयॉर्क में भारत दिवस परेड भारतीय समुदाय की ताकत और जीवंतता का प्रमाण है। यह पहली बार है जब मैंने किसी विदेशी धरती पर भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया। मैं इस खास दिन के लिए काफी उत्सुक और उत्साहित था। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने पर मैं खुद को काफी भाग्यशाली मानता हूं। यह कार्यक्रम न्यूयॉर्क के मैडिसन एवेन्यू में आयोजित किया गया था और इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन (एफआईए) द्वारा किया गया था। इंडिया डे परेड एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हर साल हजारों लोग झांकियों, पारंपरिक नृत्यों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ जश्न मनाने के लिए शामिल होते हैं। एफआईए चार दशकों से अधिक समय से इंडिया डे परेड का आयोजन कर रही है। इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देना है।

**'इंडिया डे परेड' में बने 'गेस्ट ऑफ ऑनर'**

**'स्त्री 2' में रुद्र भैया की भूमिका में पंकज मचा रहे धमाल**

'स्त्री 2' में पंकज त्रिपाठी रुद्र भैया की भूमिका में छा रहे हैं। यह फिल्म भारत में 200 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होने के लिए तैयार है। फिल्म ने अब तक भारत में 191 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। यह फिल्म मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की 5वीं किस्त है और 2018 की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'स्त्री' का सीक्वल है। फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अभिषेक बनर्जी और अपारशक्ति खुराना भी हैं।

# सरकार ने मांगें नहीं मानीं तो उग्र होगा छात्र आंदोलन : रोहित

**» आईबीपीएस और एमपीएससी परीक्षा की तारीख एक दिन होने से नाराज हैं युवा**

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। आईबीपीएस परीक्षा और एमपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिन आयोजित किए जाने के खिलाफ महाराष्ट्र पुणे में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को शरद पवार ने समर्थन दिया है। इसके घटक दल एनसीपी-एसपी के नेता रोहित पवार भी छात्रों के साथ प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं और वह सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पर जल्द फैसला लिया जाए। शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने कहा, परसों से विद्यार्थी खुद के हक के लिए लड़ रहे हैं।

आंदोलन की भूमिका उन्होंने ली है। कल रात में 15 से 20 हजार विद्यार्थी आए थे। उनकी मांग थी कि एमपीएससी परीक्षा में कृषि विषय को शामिल किया जाए। इसके अलावा बैंकिंग की परीक्षा और एमपीएससी की परीक्षा की तारीख क्लैश हो रही है। रोहित पवार ने कहा, दो महीने से मंत्री और अधिकारियों के पास विद्यार्थी जा रहे हैं लेकिन सरकार से सकारात्मक नतीजा ना आने के कारण आंदोलन हो रहा है। यह निर्णय बहुत छोटा है और तत्काल लिया जा सकता है। दक्षिण के कुछ राज्यों ने निर्णय लिया है। महाराष्ट्र सरकार विद्यार्थियों की अनदेखी कर रही है। रोहित पवार ने एक्स पर धरने की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, सरकार में मंत्रियों और अधिकारियों ने सुबह की सैर, स्नान, चाय और नाश्ता किया होगा। इसलिए छात्रों की मांग को तुरंत मानने के लिए अधिसूचना जारी की जानी चाहिए, नहीं तो दो दिनों से सड़कों पर उतरे छात्रों का आंदोलन इतना उग्र हो जाएगा कि सरकार उनके हाथ में आ जाएगी।

## कहा- विद्यार्थियों के हाथ आ जाएगी सरकार

**शरद पवार का छात्रों को समर्थन**

राकांपा-एसपी प्रमुख शरद पवार महाराष्ट्र में 25 अगस्त को होने वाली एमपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर पुणे में प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों का पक्ष लिया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी भी दी की अगर उन्होंने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया तो वे (शरद पवार) प्रदर्शन में शामिल हो जाएंगे। शरद पवार ने कहा, एमपीएससी परीक्षा देने वाले छात्रों के हितों पर विचार करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि, ऐसा लग रहा है कि सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। कल तक अगर सरकार अपने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया तो मैं प्रदर्शन वाले स्थान पर जाऊंगा और छात्रों को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन में हिस्सा लूंगा।

# अभिनेता थलापति विजय की राजनीति में एंट्री

**» स्टार ने पार्टी का फ्लैग और एंथम किया लॉन्च**

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चेन्नई। तमिल सिनेमा के मेगास्टार विजय को फैंस थलापति के नाम से जानते हैं। एक्टर की अब राजनीति में एंट्री हो गई है। इस साल की शुरुआत में, फरवरी में, विजय ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी तमिझागा वेट्रिकाझागम (टीवीके) के गठन की घोषणा की थी। गुरुवार को उन्होंने कदम और आगे बढ़ाते हुए चेन्नई के पयानूर में पार्टी मुख्यालय में एक भव्य कार्यक्रम में, आधिकारिक तौर पर पार्टी के झंडे और प्रतीक को लॉन्च कर दिया। इस अवसर पर पार्टी के एंथम को भी लॉन्च किया गया।

तमिलनाडु की राजनीति में फिल्मी सितारों का प्रवेश एक जाना-माना रास्ता है। एम.जी. रामचंद्रन (एमजीआर) से लेकर जयललिता तक और शिवाजी गणेशन से लेकर रजनीकांत, कमल हासन और विजयकांत तक, कई दिग्गज अभिनेता सिल्वर स्क्रीन से राजनीति के मंच पर आ चुके हैं। इस लिस्ट में अब थलापति विजय का नाम भी शामिल हो गया है।

**अपना जीवन तमिलनाडु के लोगों कों समर्पित करना चाहता हूं : विजय**

विजय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी जल्द ही एक विशाल सम्मेलन आयोजित करेगी, जहां वे टीवीके के सिद्धांतों और लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि वे पहले अपने लिए जीते थे, लेकिन अब वे अपना जीवन तमिलनाडु के लोगों के लिए समर्पित करना चाहते हैं।

# एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की धमकी

**» तिरुवनंतपुरम पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग**

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

तिरुवनंतपुरम। मुंबई से तिरुवनंतपुरम पहुंची एअर इंडिया की फ्लाइट में बम की धमकी मिली है। बम की धमकी मिलने के बाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित की गई है। जानकारी के मुताबिक एअर इंडिया की फ्लाइट एआई 657 को एयरपोर्ट पर सुरक्षित तरीके से लैंड करवाया गया है।

इसके बाद से ही फ्लाइट को आइसोलेशन में रखा गया है। फ्लाइट में कुल 135 यात्री और की सवार थे, जिन्हें सुरक्षित उतार लिया गया है। एयरपोर्ट ने बताया 22 अगस्त को सुबह 7 :30 बजे बम की धमकी की सूचना एआई 657 ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ शेयर की।

# पुरानी संस्कृति को संजोना जरूरी: पारुल शर्मा

**» उषा महेश फाउंडेशन ने मनाया कजरी दंगल**

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। उषा महेश फाउंडेशन के तत्वाधान में आज पारूल्स ग्रामोफोन में कजरी दंगल का आयोजन हुआ। कजरी तीज के एक दिन पहले कजरी गायन, रतजगा और जलेबा खाने की प्रथा अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। पारुल शर्मा ने बताया की इसी संस्कृति को वापस लाने और संजोने का काम हम फाउंडेशन के अंतर्गत करते हैं।

गौरा और पार्वती टीम में जबरदस्त भिड़ंत हुई जिसको निर्याणक मंडल, सीमा श्रीवास्तव व कामिनी मिश्र ने समझा, परखा। अंत में टीम गौरा जीती। पार्वती टीम सिर्फ एक नंबर से पीछे थी। लखनऊ से संगीत, थिएटर, कला व साहित्य जगत की कई गणमान्य हस्तियां मौजूद थीं। डा. भक्ति शुक्ल, माया यादव, सुषमा प्रकाश, गुंजन जैन, जागृति सिंह, बिनीता शुक्ला, प्रगति सिंह, सांगला दीक्षित, ममता सिंह, सुशीला लाल, कमला देशमुख, नीलम यादव, ऋतु वर्मा, रूमा खन्ना, शालिनी सिंह इत्यादि।

**पारंपरिक आयोजनों ने लोगों का मन मोहा**

पारंपरिक भोजन जैसे सत्तू कचौरी, आलू टमाटर का झोल, फरे, सिल बट्टे की चटनी, दही बड़ा, जलेबी का लुत्फ उठाया गया। पैरों में महावर और हाथों में मेंहदी इत्यादि लगवाकर सभी ने झूला झूलकर कजरी तीज का आनंद लिया।

# जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल के दर्द को मिटाना ही लक्ष्य : राहुल

**» श्रीनगर में बोले नेता प्रतिपक्ष- जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व जरूरी**

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

श्रीनगर। गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने श्रीनगर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, जैसे ही हमें पता चला कि चुनाव होने वाले हैं तो मल्लिकार्जुन खरगे और हम मिले और हमने तय किया कि हमें सबसे पहले जम्मू-कश्मीर आना चाहिए।

हम जम्मू और कश्मीर के लोगों और हिंदुस्तान के हर राज्य के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व व राज्य का दर्जा सबसे जरूरी चीज है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को जम्मू-कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद कई बार केंद्रीय शासित प्रदेश को राज्य में बदला गया है लेकिन एक ही उदाहरण है जब राज्य का दर्जा छीनकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। हम यह संदेश देना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व हमारे लिए और देश के लोगों के लिए जरूरी है इसलिए हम यहां पहले आए हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि मैं लोकतंत्र की रक्षा पूरे देश में करता हूं लेकिन मेरे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल के दर्द को मिटाना ही लक्ष्य है। जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है उसे मैं, मल्लिकार्जुन खरगे, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे।

## डरने वालों का साथ मत दीजिए : मल्लिकार्जुन खरगे

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि उनका रिश्ता जम्मू-कश्मीर से है। इसलिए हमारी अपेक्षा है कि जम्मू-कश्मीर की जनता आने वाले चुनाव में जरूर हमारा साथ देगी लेकिन आपको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। भाजपा हमेशा तय करती है कि कहां से चुनाव शुरू करने हैं, किस ढ़ंग से लोगों को चुनकर लाना है और उनका सारा गुस्सा कांग्रेस के ऊपर है, दूसरी पार्टियों के ऊपर नहीं है क्योंकि दूसरी पार्टियां लड़ती ही नहीं हैं। लड़ने वाला एक ही बहादुर व्यक्ति है और वो हैं राहुल गांधी। इसलिए डरने वालों का साथ मत दीजिए। हम लोग, हमारी पार्टी आपके साथ है और साथ रहेगी। हमें केवल वोटों के लिए आपकी जरूरत नहीं है बल्कि हमें इस देश को बचाने के लिए आपका वोट चाहिए।

# डॉक्टरों से काम पर लौटने की सुप्रीमकोर्ट ने की अपील

**» सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी- सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा ऐसे कैसे काम करेगा**

**» सीबीआई और कोलकाता पुलिस ने सीलबंद लिफाफे में सौंपी स्थिति रिपोर्ट**

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हुई हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इससे पहले सीबीआई और कोलकाता पुलिस ने सीलबंद लिफाफे में अपनी स्थिति रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। मामला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के पास है। इसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने बीती 20 अगस्त को मामले का स्वत: संज्ञान लिया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर्स समेत स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को काम पर लौटने दें और एक बार जब वे ड्यूटी पर लौट आएंगे तो अदालत अधिकारियों को उन पर कार्रवाई न करने के लिए मनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं लौटेंगे तो सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा कैसे काम करेगा।

## सीजेआई ने बताया अस्पताल के फर्श पर सोने का वाकया

सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी एक कहानी भी सुनाई। उन्होंने बताया कि वह एक बार एक सार्वजनिक अस्पताल के फर्श पर सोए थे, जब उनके एक रिश्तेदार की तबीयत खराब थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

## केंद्र को दुष्कर्म विरोधी कानून बनाना चाहिए : अभिषेक बनर्जी

टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि दुख की बात यह है कि अभी तक एक स्थायी समाधान पर चर्चा नहीं हुई। हमें मजबूत कानून की जरूरत है। राज्य सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए और केंद्र पर दुष्कर्म विरोधी कानून के लिए दबाव बनाना चाहिए। बनर्जी ने कहा, पिछले 10 दिनों से देश आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल घटना को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं।

## कोलकाता केस में लीपापोती की कोशिश की गई : सीबीआई

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हुई हत्या के मामले में स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। रिपोर्ट में सीबीआई ने बताया है कि अपराध स्थल से छेड़छाड़ की गई। इस पूरे मामले में लीपापोती की कोशिश की गई। सीबीआई ने अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज किए जाने पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने बीती 20 अगस्त को स्वत: संज्ञान लेकर आरजी कर कॉलेज की घटना पर सुनवाई की थी। इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई और बंगाल सरकार से घटना की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट अदालत में जमा करन का निर्देश दिया था।

**विरोध प्रदर्शन** हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा जांच कराए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस आज देशभर में प्रदर्शन कर रही है। इसी के तहत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में यूपी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के अलावा कई नेता मौजूद रहे। जिनसे पुलिसकर्मियों से काफी नोकझोंक भी हुई।

# स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों ने डिप्टी सीएम के आवास का किया घेराव

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों ने अपनी नौकरी की सुरक्षा के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास का घेराव किया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने अपनी संविदा की अवधि बढ़ाने और स्थायी नियुक्ति की मांग की है।

कर्मचारियों का कहना है कि कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन अब उनकी संविदा समाप्त कर दी गई है। इस स्थिति में, वे सड़क पर आ गए हैं और बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वे पिछले 15 दिनों में स्थानीय अधिकारियों के पास कई बार अपनी समस्या लेकर गए हैं, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है।

# आंध्र प्रदेश की फार्मा फैक्ट्री में आग, 18 लोगों की मौत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश में अनाकापल्ले जिले की एक फार्मा कंपनी में बुधवार (21 अगस्त) आग लग गई। हादसे में पहले 18 मौतों की जानकारी सामने आई। देर रात प्रशासन ने 17 लोगों की मौत की पुष्टि की। 36 लोग जख्मी हैं। सभी को जिले के एनटीआर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना अच्युतापुरम स्थित फार्मा कंपनी एस्किएंटिया के प्लांट में हुई।

**सीएम नायडू पीड़ितों से मिले**

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पहले कंपनी के रिएक्टर के पास आग दिखी, फिर तेज धमाका हुआ। इससे बिल्डिंग के पहले फ्लोर का स्लैब ढह गया। लोगों ने कहा कि घायलों की संख्या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि फैक्ट्री में 381 से ज्यादा कर्मचारी दो शिफ्ट में काम करते हैं। घटना के समय ज्यादातर कर्मचारी लंच पर गए थे।

अधिकारियों ने बताया कि सॉल्वेंट ऑयल पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर पंप किया जा रहा था, तभी लीकेज हुआ और आग लग गई। इससे 500 किलोलीटर के कैपेसिटर रिएक्टर में ब्लास्ट हुआ। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि घटना की हाई लेवल जांच की जाएगी। अगर फैक्ट्री मैनेजमेंट की लापरवाही सामने आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित एवं 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। संपादक - संजय शर्मा, विधि सलाहकार: सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, वित्तीय सलाहकार: संदीप बंसल, कार्टूनिस्ट: हसन जैदी, दूरभाष: 0522- 4078371 | Email: daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in
RNI-UPHIN/2015/62233 डाक पंजी. सं- SSP/LW/NP-495/2018-2020 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।